

DAILY CURRENT AFFAIRS

By



SOURCES



Date: 5 Apr. 2024

Important News Articles

1. वर्ष 2022-24 में 55 कंपनियों का चुनावी बॉन्ड दान 7.5% की सीमा से ऊपर रहा- द हिंदू
2. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रणाली- द हिन्दू
3. भारत की शिक्षा प्रणाली में अंतराल से सम्बंधित मामला - द हिंदू
4. राजनीतिक संबद्धता नए सैनिक स्कूलों की चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती: रक्षा मंत्रालय- द हिंदू
5. खगोलशास्त्री चंद्रमा की कक्षा में भारत की प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन को लगायेंगे - द हिंदू
6. भारत पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का सामरिक भंडारण बनाएगा- द हिंदू
7. EV सब्सिडी: ओला इलेक्ट्रिक एवं अन्यो को MHA से मैनुअल प्रारूप में प्रमाण पत्र मिले - द हिंदू
8. पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में लॉरेल पेड़ की छाल काटने पर तने से पानी निकला- इंडियन टुडे

Editorials, Gists and Explainers

9. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से सम्बंधित मामला - द हिंदू
10. उत्तराखंड सरकार GLOF के जोखिम का मूल्यांकन करेगी -इंडियन एक्सप्रेस

Quick Look

1. पैरा फसल प्रणाली
2. स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH)
3. अग्नि-प्राइम मिसाइल
4. पर्पल स्ट्राइप्ड जेलिफ़िश
5. एक्साइज ड्यूटी

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. वर्ष 2022-24 में 55 कंपनियों का चुनावी बॉन्ड दान 7.5% की सीमा से ऊपर रहा- द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

समाचार:

- चुनावी बॉन्ड (EB) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 (1) में निहित एक प्रावधान को हटाने को "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन" माना था।
- इस प्रावधान ने राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान को सक्षम बनाया

मुख्य बिंदु

- प्रावधान ने कॉर्पोरेट दान को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दाता कंपनियों के औसत शुद्ध लाभ के 7.5% की सीमा तक सीमित कर दिया था।
- वित्त अधिनियम, 2017 ने प्रावधान को हटा दिया था।
- रद्द की गई 7.5% सीमा से ऊपर दान की गई कुल राशि ₹1,377.9 करोड़ थी, जो उनके कुल दान ₹1,993 करोड़ का 69% से अधिक थी।
- अकेले सत्तारूढ़ दल को कुल दान का लगभग 71%, या ₹1,414 करोड़ प्राप्त हुआ।
- विशेष रूप से, इन फर्मों के वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक के ईबी दान डेटा का मिलान वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक के उनके वित्तीय डेटा से किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2017

- इसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA), आयकर अधिनियम, 1961 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किया।
- संशोधनों ने चुनावी बॉन्ड को कंपनियों के लिए दान सीमा को पूरी तरह से हटाकर राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर कई प्रतिबंधों में कटौती करने की अनुमति दी गई है,
 - और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की घोषणा करने और उसका रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकताओं को हटाना।

कंपनी अधिनियम, 2013

- अधिनियम की धारा 182 में कई बदलाव किए गए, जिसमें उन निषेधों और प्रतिबंधों का विवरण दिया गया है जिनका किसी कंपनी को राजनीतिक योगदान देते समय पालन करना चाहिए।
- संशोधन से पहले, धारा 182(1) में एक कंपनी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दान की जाने वाली धनराशि की सीमा निर्धारित की गई थी।
 - इसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 7.5% तक सीमित कर दिया गया।
- धारा 182(3) के तहत कंपनी को किसी भी राजनीतिक दल को दी गई किसी भी राशि का खुलासा करने के साथ-साथ दान की गई राशि का विवरण और प्राप्तकर्ता पार्टी का नाम भी बताना होगा।
- केवल योगदान की गई कुल राशि का खुलासा किया जाना था
 - कंपनी को अब यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसने किस राजनीतिक दल को दान भेजा है, न ही विशिष्ट राशि।
- अदालत ने इस संशोधन को रद्द कर दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति चुनावी प्रक्रिया में कंपनियों के अनियंत्रित प्रभाव को अधिकृत करती है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- धारा 182(3)
- कंपनी अधिनियम, 2013

2. राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रणाली- द हिन्दू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका।

प्रीलिम्स टेकअवे

- चुनाव चिन्ह
- ECI

समाचार:

- नाम तमिलर काची (NTK) जिसने वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में तमिलनाडु में क्रमशः 3.9% और 6.5% वोट हासिल किए, को एक नया सामान्य प्रतीक (माइक) आवंटित किया गया है।
- वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में 1.09% और 0.99% वोट हासिल करने वाली विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) को एक सामान्य प्रतीक (Pot) से वंचित कर दिया गया है।
- इससे 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों' को चुनाव चिन्ह आवंटन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

नियम

- भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के प्रावधानों के तहत एक पार्टी को 'राष्ट्रीय' या 'राज्य' पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है।
- राज्य स्तर पर मान्यता के मानदंड शामिल हैं
 - प्रत्येक 25 सीटों या 3% विधान सभा सीटों के लिए एक लोकसभा सीट जीतना या
 - 6% वोटों के साथ एक लोकसभा या दो विधानसभा सीटें जीतना
 - आम चुनाव में डाले गए 8% वोट हासिल करना।
- ECI द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।
- सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां एक बड़ी आबादी अभी भी निरक्षर है, मतदान प्रक्रिया में प्रतीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक आरक्षित प्रतीक होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।
- पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव के दौरान मुफ्त प्रतीकों में से एक को सामान्य प्रतीक के रूप में आवंटित किया जाता है
 - यदि वह पार्टी दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में या किसी राज्य की विधानसभा में 5% सीटों पर, जैसा भी मामला हो, चुनाव लड़ती है।

मौजूदा मामला क्या है?

- प्रतीक आदेश के नियम 10 B में प्रावधान है कि एक सामान्य मुक्त प्रतीक की रियायत दो आम चुनावों के लिए 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी' को उपलब्ध होगी।
- इसके अलावा, एक पार्टी किसी भी बाद के आम चुनाव में एक सामान्य प्रतीक के लिए पात्र होगी यदि उसने पिछले अवसर पर राज्य में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे जब पार्टी ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।
- हालाँकि ऐसी गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी को हर बार निर्धारित प्रारूप में प्रतीक चिन्ह के लिए आवेदन करना चाहिए।
- यह आवेदन लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय किया जा सकता है।
- उसके बाद प्रतीकों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाता है।

3. भारत की शिक्षा प्रणाली में अंतराल से सम्बंधित मामला - द हिन्दू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- ASER
- ILO

समाचार:

- जनवरी में जारी ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में पाया गया कि आधे से अधिक लोगों को बुनियादी गणित में संघर्ष करना पड़ा, एक ऐसा कौशल जिसमें उन्हें कक्षा 3 और 4 में महारत हासिल करनी चाहिए थी।
- नागरिक समाज संगठन प्रथम द्वारा 14 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया था।

मुख्य बिंदु

- 26 राज्यों के 28 जिलों में किए गए घरेलू सर्वेक्षण में 30,000 से अधिक छात्रों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणित क्षमताओं का आकलन किया गया और पता चला कि इस आयु वर्ग के लगभग 25% छात्र अपनी स्थानीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं।
- जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ती गई।
- जबकि 14 साल के 3.9% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 18 साल के बच्चों के लिए यह आंकड़ा बढ़कर 32.6% हो गया।
- इसके अलावा, केवल 5.6% ने व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना था।
- मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार हालिया भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 सहित बाद के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हालांकि सभी सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ है,
 - लेकिन सामाजिक समूहों के बीच पदानुक्रम कायम है, अनुसूचित जनजातियां अभी भी सबसे अधिक वंचित हैं।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन दर महत्वपूर्ण ड्रॉपआउट दिखाती है और लैंगिक अंतर भी अधिक है।
- ST बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, "सुधारित शिक्षाशास्त्र" की आवश्यकता है
 - मातृभाषा में शिक्षा और जनजातीय बोलियों में सहायक सामग्री।
- स्कूल की गतिविधियों और विद्यार्थियों के जीवन के बीच तालमेल होना जरूरी है

4. राजनीतिक संबद्धता नए सैनिक स्कूलों की चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती: रक्षा मंत्रालय- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- नए सैनिक स्कूलों की योजना "सुविचारित" है और आवेदक संस्थान की "राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता या अन्यथा" चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है
- रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूल सार्वजनिक स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले विशेष आवासीय विद्यालय हैं।

मुख्य बिंदु

- **CBSE संबद्धता:** ये स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हैं, जो एक मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करते हैं।
- **सरकारी अनुदान:** केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्त पोषित, सैनिक स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाते हैं।

उत्कृष्टता की विरासत

- **वर्ष 1961 में स्थापित:** राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के लिए लड़कों को तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित, सैनिक स्कूलों का शैक्षणिक और सैन्य उत्कृष्टता का एक लंबा इतिहास है।
- **सर्वांगीण विकास पर फोकस:** ये स्कूल सर्वांगीण व्यक्तियों को तैयार करने के लिए शिक्षाविदों से आगे बढ़कर शारीरिक फिटनेस, मानसिक लचीलेपन और नेतृत्व गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **राष्ट्रीय उपस्थिति:** पूरे भारत में 33 स्कूलों के साथ, सैनिक स्कूल विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को अवसर प्रदान करते हैं।
- **नवीनतम विस्तार:** एक नई पहल का लक्ष्य गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 अतिरिक्त सैनिक स्कूल स्थापित करना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ हो सके।

भविष्य निर्माण:

प्रीलिम्स टेकअवे

- गैर सरकारी संगठन
- सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय

- **समग्र शिक्षा:** सैनिक स्कूलों का लक्ष्य ऐसे युवाओं की एक पीढ़ी तैयार करना है जो अकादमिक रूप से मजबूत, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, आत्मविश्वासी और मजबूत नेतृत्व गुणों वाले हों।
- **देशभक्ति और आत्मनिर्भरता:** ये स्कूल अपने छात्रों में देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करते हैं, उन्हें जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के नेता बनने के लिए तैयार करते हैं।
- **सैनिक स्कूल एक अद्वितीय शैक्षिक मार्ग** प्रदान करते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को ऐसे समृद्ध व्यक्तियों को आकार देते हैं जो राष्ट्र के लिए सार्थक योगदान दे सकें।

सामान्य अध्ययन III

5. खगोलशास्त्री चंद्रमा की कक्षा में भारत की प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन को लगायेंगे - द हिंदू

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

प्रीलिम्स टेकअवे

- कॉस्मिक रे
- प्रत्यूष (PRATUSH)

समाचार:

- खगोलविद चंद्रमा पर और उसके चारों ओर कक्षा में **उच्च-रिज़ॉल्यूशन दूरबीनें** तैनात करके **ब्रह्मांड** पर एक नई योजना पर काम करने की उम्मीद कर रहे हैं।
- **दुनिया** भर के **खगोलविदों** की ओर से ऐसा करने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं, जिनमें **भारत** का एक **प्रस्ताव** भी शामिल है जिसे **प्रत्यूष (PRATUSH)** कहा जाता है।

मुख्य बिंदु

- **RRI** और इसरो द्वारा निर्मित **भारत की प्रत्यूष (PRATUSH) दूरबीन** का उद्देश्य **ब्रह्मांड** के शुरुआती दिनों के रहस्यों को उजागर करना है।
- पृथ्वी के हस्तक्षेप से बचने के लिए यह **रेडियो टेलीस्कोप चंद्रमा** के दूर की ओर स्थित होगा, **चंद्रमा** की ओर **प्रक्षेपित** होने से पहले यह **पहले पृथ्वी** की परिक्रमा करेगा।
- **प्रत्यूष (PRATUSH)** सबसे पहले **तारों और आकाशगंगाओं** से आने वाले **हल्के रेडियो संकेतों** को सुनेगा।
- इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये पहले तारे कब उभरे, वे कैसे थे, और ब्रह्मांड की **"कॉस्मिक डॉन "** के दौरान उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रकृति क्या थी।
- **कॉस्मिक नोइज़** के बीच इन कमजोर संकेतों को पकड़ने के लिए **दूरबीन विशेष उपकरणों** से सुसज्जित है।
- इन उपकरणों में एक **वाइडबैंड एंटीना**, एक **सेल्फ-कैलिब्रेटिंग रिसेवर** और एक **डिजिटल सहसंबंधक** शामिल हैं।
- लक्ष्य कुछ **मिलीकेल्विन** की **संवेदनशीलता** प्राप्त करना है, जिससे **विकृतियों** के बिना स्पष्ट पता लगाना संभव हो सके।

6. भारत का पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का सामरिक भंडारण - द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

समाचार:

- भारत किसी भी **आपूर्ति व्यवधान** के खिलाफ **बीमा** के रूप में **भंडार** को बढ़ाने के प्रयासों के तहत अपना पहला **वाणिज्यिक कच्चे तेल सामरिक भंडारण** बनाने की योजना बना रहा है।

प्रीलिम्स टेकअवे

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

मुख्य बिंदु

- **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL)**, देश में **सामरिक पेट्रोलियम भंडार** के निर्माण और संचालन के लिए **सरकार** द्वारा बनाई गई एक **SPV** है।
 - **कर्नाटक** के **पादुर** में **2.5 मिलियन टन भूमिगत भंडारण** के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं
- **ISPRL** ने पहले चरण में **तीन स्थानों** पर **भूमिगत बिना लाइन वाली चट्टानी गुफाओं** में एक **सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व** बनाया था।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)

- ये कच्चे तेल के भंडार हैं जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय भी कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखे जाते हैं।
- ये भूमिगत भंडारण सुविधाएं देश की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (I.E.P.) समझौते की शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) से संबंधित प्रत्येक राष्ट्र को अपने शुद्ध तेल आयात के न्यूनतम 90 दिनों के बराबर तेल का आपातकालीन भंडार बनाए रखना आवश्यक है।
- वर्ष 2017 में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के भीतर एक सहयोगी सदस्य का दर्जा हासिल किया।

7. EV सब्सिडी: ओला इलेक्ट्रिक एवं अन्यो को MHI से मैनुअल प्रारूप में प्रमाण पत्र मिले - द हिंदू

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

समाचार:

- ओला इलेक्ट्रिक, TVS मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय (MHI) से मैनुअल प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम
- इलेक्ट्रिक वाहन

मुख्य बिंदु

- हालांकि EMPS के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार नहीं है, लेकिन कंपनियों को हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय (MHI) से मैनुअल प्रारूप में 'आगे बढ़ने' का प्रमाण पत्र मिल रहा है।
- कंपनियों के बीच राहत है क्योंकि 3 अप्रैल से निर्मित वाहन इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024:

- भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e2W) और तिपहिया वाहनों (e3W) की खरीद को बढ़ावा देने के लिए EMPS 2024 पेश किया है।
- 5 अरब रुपये के बजट के साथ, यह FAME-2 योजना की जगह लेगी और अप्रैल से जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद इसे बदले जाने या बढ़ाए जाने की संभावना है।
- मुख्य लक्ष्य सब्सिडी पर उद्योग की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करते हुए e2Ws और e3Ws को अपनाना है।
- इस योजना में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e4Ws) और ई-बसें शामिल नहीं हैं।

8. पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में लॉरेल पेड़ की छाल काटने पर तने से पानी निकला- इंडियन टुडे

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

समाचार:

- आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू जिले में वन विभाग के अधिकारियों ने एक भारतीय लॉरेल पेड़ की छाल काट दी, जिससे पानी निकल रहा था।
- वन अधिकारियों ने पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ की छाल काट दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेड़ गर्मियों में पानी जमा करता है।

भारतीय लॉरेल वृक्ष

- इसे इसके वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया एलिफिका (सिन टी टोमेंटोसा) से भी जाना जाता है, यह दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी एक बहुमुखी पेड़ है।

सामान्य नाम और उपस्थिति

- भारतीय लॉरेल के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभिन्न नाम हैं जैसे असना, साज, मारुथम, मैटी, ऐन, तौक्क्यन और आसन।

आवास और वितरण

प्रीलिम्स टेकअवे

- भारतीय लॉरेल वृक्ष
- आंध्र प्रदेश

- मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में 1000 मीटर की ऊंचाई तक शुष्क और नम पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है।
- यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को शामिल करने वाले एक व्यापक क्षेत्र का मूल वृक्ष है।
- मजबूत लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, अलमारियाँ, नाव निर्माण, सजावटी लिबास और यहां तक कि गिटार फ्रेटबोर्ड जैसे संगीत वाद्ययंत्र के लिए किया जाता है।
- पत्तियां एंथेरिया पफिया रेशमकीटों के लिए एक खाद्य स्रोत हैं, जो टसर रेशम का उत्पादन करते हैं, जो एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली रेशम है।
- छाल का औषधीय उपयोग होता है, जिसमें डायरिया का इलाज भी शामिल है, और इसका उपयोग ऑक्सालिक एसिड निकालने के लिए किया जा सकता है।
- छाल और फल पायरोगैलोल और कैटेचोल का स्रोत हैं, जिनका उपयोग चमड़े की रंगाई और टैनिंग के लिए किया जाता है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. राज्यों की उधार लेने की शक्तियों से सम्बंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ।

समाचार:

- केरल सरकार ने राज्य उधार लेने की शक्ति के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य की उधारी राज्य की आय या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% तक सीमित होनी चाहिए।
- केरल राज्य का तर्क है कि उसकी उधार लेने की शक्तियों में कटौती करके, केंद्र राज्य की कुछ बुनियादी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को कम कर रहा है और संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है।
- संविधान भारत की संघीय सरकार (संघ) और राज्य सरकारों के बीच व्यय जिम्मेदारियों को विभाजित करता है।
- **टैक्स में वृद्धि:** अधिकतर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **स्पेंडिंग:** अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है (संघ के ₹2,230 बिलियन की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹19,182 बिलियन)।

सामाजिक सेवाओं बनाम अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दें:

- केंद्र सरकार रक्षा (सामाजिक सेवाओं से लगभग दोगुना) और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा (सामाजिक सेवाओं से 2.4 गुना) पर अधिक खर्च करती है।
- राज्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में सामाजिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस खर्च से धीमी ग्रामीण आय वृद्धि को संबोधित करने में मदद मिली है।

केरल: केस स्टडी

- उन्होंने अपने बजट का 40-50% सामाजिक क्षेत्रों (1960-2000) को समर्पित किया, जिससे महत्वपूर्ण विकास हुआ।
- हालाँकि, उनका सामाजिक व्यय अनुपात हाल ही में स्थिर हो गया है, जबकि अन्य राज्यों ने अपना बढ़ा दिया है।
- केरल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय सरकारों को सौंपता है, जो उन्हें अभी भी सामाजिक खर्च में राष्ट्रीय औसत से ऊपर रख सकता है।

चुनौतियाँ और विचार:

- राज्यों को तीन स्रोतों करें, संघ हस्तांतरण और उधार से धन मिलता है।
- केरल ने आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए महामारी के दौरान भारी उधार लिया।
- कम केंद्रीय हस्तांतरण और स्थिर कर राजस्व ने केरल को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर किया।

केरल द्वारा बढ़ती उधारी के लिए तर्क:

- उच्च सामाजिक व्यय ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- केरल की उच्च बचत दर के साथ घरेलू संस्थानों से उधार लेना लाभदायक हो सकता है।
- उधार ली गई धनराशि का प्रभावी उपयोग विकास का एक अच्छा चक्र बना सकता है।

केरल के खर्च को लेकर चिंताएं:

- सामाजिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जिससे संभावित रूप से नई पहल के लिए धन सीमित हो जाता है।
- कम पूंजीगत व्यय (बुनियादी ढांचा) भविष्य की वृद्धि में बाधा बन सकता है।

आगे की राह:

- केरल का तर्क है कि उधार लेने पर **प्रतिबंध संघवाद** का उल्लंघन करता है और **वित्तीय प्रतिबद्धताओं** को पूरा करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- बढ़ती **आबादी और युवाओं** के बाहर प्रवास के कारण अन्य राज्यों को भी जल्द ही इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इन मुद्दों के समाधान के लिए **केंद्र और राज्य सरकारों** को सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **केरल को संघ** को यह समझाने की जरूरत है कि उनकी उधारी एक **दीर्घकालिक निवेश** है, न कि केवल त्वरित समाधान।

10. उत्तराखंड सरकार GLOF के जोखिम का मूल्यांकन करेगी -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

समाचार:

- **उत्तराखंड सरकार** ने क्षेत्र में **पांच संभावित खतरनाक हिमनद झीलों** से उत्पन्न खतरे का **मूल्यांकन** करने के लिए **विशेषज्ञों की दो टीमों** का गठन किया है।
- ये झीलें **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)** से ग्रस्त हैं, जिस तरह की **घटनाओं के परिणामस्वरूप** हाल के वर्षों में **हिमालयी राज्यों** में कई आपदाएँ हुई हैं।

मुख्य बिंदु

- जोखिम मूल्यांकन अभ्यास का लक्ष्य GLOF घटना की संभावना को कम करना और उल्लंघन की स्थिति में राहत और निकासी के लिए अधिक समय प्रदान करना है।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)

- **ग्लेशियर रिट्रीट, लेक फॉर्मेशन** : जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं, वे अपने पीछे अवसाद छोड़ जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है और हिमनद झीलें बन जाती हैं।
- ये झीलें ऊंचे पहाड़ों और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे आम हैं।
- **झीलों के प्रकार**: दो मुख्य प्रकार हैं: बर्फ-संपर्क झीलें (ग्लेशियर को छूने वाली) और दूरस्थ झीलें (अधिक दूर लेकिन फिर भी ग्लेशियरों से प्रभावित)।
- **GLOF खतरा**: अधिकांश हिमनदी झीलें बर्फ या ढीली चट्टान के अस्थिर बांधों द्वारा अनिश्चित रूप से रोकी जाती हैं।
- यदि ये बांध टूट जाते हैं, तो GLOF नामक एक विशाल बाढ़ पहाड़ों से नीचे गिरती है, जिससे विनाशकारी क्षति होती है।

GLOF को क्या ट्रिगर करता है?

- **आइस कैल्विंग**: बर्फ के बड़े टुकड़े ग्लेशियरों को तोड़कर झील में गिर सकते हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
- **भूस्खलन और हिमस्खलन**: ये घटनाएँ झील को बनाए रखने वाले बांध को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे अचानक पानी छोड़ा जा सकता है।

GLOFs का विनाशकारी प्रभाव

- **फ्लड ऑफ़ फरी** : GLOF भारी मात्रा में पानी, तलछट और मलबा छोड़ते हैं, जिससे पूरी घाटियाँ अविश्वसनीय तरीके से नष्ट हो जाती हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर ऑबलिटरेटेड**: सड़कों, पुलों और इमारतों का इन बाढ़ों से कोई मुकाबला नहीं है, जिससे व्यापक विनाश हुआ।
- **जीवन और आजीविका की हानि**: GLOF जीवन की दुखद हानि और समुदायों को तबाह कर सकता है।

बढ़ता हुआ खतरा: जलवायु परिवर्तन और विकास

- **मेल्टिंग ऑन द राइज़** : बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे विशेष रूप से हिमालय में अधिक और बड़ी हिमनद झीलें बन रही हैं।
- **खतरनाक स्थानों में डेवलपमेंट** : उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण से GLOF के खतरे और बढ़ जाते हैं।

भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग जोखिम में

- एक हालिया अध्ययन नेचर में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग GLOF खतरों का सामना करते हैं, बावजूद इसके कि इन क्षेत्रों में अन्य स्थानों की तुलना में कम हिमनद झीलें हैं।
- इन क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अधिक GLOF-प्रवण क्षेत्रों में से एक बनाता है।

जोखिम मूल्यांकन: खतरे को कम करना

- **शीघ्र चेतावनी सिस्टम**: भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) GLOF जोखिमों को कम करने और उल्लंघन होने पर तेजी से निकासी की अनुमति देने के लिए संभावित खतरनाक हिमनद झीलों की पहचान कर रहा है।
- **हाई अलर्ट पर उत्तराखंड**: हिमालयी राज्यों में 188 संभावित जोखिम भरी हिमनद झीलों की पहचान की गई है, जिनमें से 13 उत्तराखंड में हैं।
- GLOF जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न एक गंभीर खतरा है।
- जोखिमों को समझकर और निवारक उपाय करके, हम उम्मीद से उनके कारण होने वाली तबाही को कम कर सकते हैं।

फैक्ट फटाफट

1. पैरा फसल प्रणाली

- उटेरा/पैरा एक प्रकार की फसल है जो आमतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रचलित है।
- यह बुआई की एक प्रकार की रिले विधि है जिसमें धान की खड़ी फसल में कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर/लथीरस/उर्दबीन/मूंग के बीज डाले जाते हैं।
- यह प्रणाली जुताई, निराई, सिंचाई और उर्वरक जैसे कृषि संबंधी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देती है, हालांकि, चावल की किस्म इस प्रणाली में दालों की उत्पादकता तय करती है।
- यह अभ्यास हमें चावल की फसल की कटाई के समय उपलब्ध बेहतर मिट्टी की नमी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जो अन्यथा जल्दी ही नष्ट हो सकती है।
- प्रायोगिक साक्ष्यों से पता चला है कि चावल की फसल की कटाई के बाद जुताई के साथ बुआई करने की तुलना में जोड़ीदार फसल से मसूर की अधिक पैदावार होती है।
- यह टिकाऊ फसल गहनता और भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका है।

2. स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH)

- स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट (SARAH) एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप है, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ है।
- इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, स्वास्थ्य के अपने अधिकारों का एहसास कराने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना है।
- इसे स्वस्थ आदतों और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है
- इसमें कैंसर, हृदय रोग सहित दुनिया में मृत्यु के कुछ प्रमुख कारणों के जोखिम कारकों की बेहतर समझ विकसित करने में लोगों की सहायता करने की क्षमता है।
- यह लोगों को तंबाकू छोड़ने, सक्रिय रहने, स्वस्थ आहार खाने और अन्य चीजों के अलावा तनावमुक्त होने के बारे में नवीनतम जानकारी तक पहुंचने में मदद कर सकता है।

3. अग्नि-प्राइम मिसाइल

- यह अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु-सक्षम नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 1,000 से 2,000 किमी की अधिकतम सीमा वाली दो चरणों वाली कनस्तरयुक्त मिसाइल है।
- यह अग्नि श्रृंखला की पिछली सभी मिसाइलों से हल्की है। इसका वजन अग्नि 3 मिसाइल से कम से कम 50 प्रतिशत कम है और इसमें नई मार्गदर्शन और प्रणोदन प्रणाली है।
- इसे सड़क और रेल मार्ग से ले जाया जा सकता है और लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे तैयारी और लॉन्च के लिए आवश्यक समय काफी कम हो जाता है। मिसाइल एक शीत प्रक्षेपण तंत्र का उपयोग करती है और इसे सैल्वो मोड में दागा जा सकता है।

4. पर्पल स्ट्राइप्ड जेलिफ़िश

- यह आमतौर पर नीले बैंगनी (मौवे) रंग में दिखाई देता है, जिसमें ग्लोब के आकार की छतरी होती है जो नारंगी भूरे रंग के मस्सों से ढकी होती है।
- यह मुख्य रूप से पेलजिक या खुले महासागर में है, हालांकि, यह प्रजाति बेंटिक और समशीतोष्ण तटीय आवासों में जीवित रह सकती है।
- यह दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और गर्म तापमान वाले समुद्रों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में पाया जाता है।
- अन्य जेलीफ़िश प्रजातियों के विपरीत, इसमें न केवल टेंटेकल्स पर, बल्कि बेल पर भी उंक होते हैं। ये बायोलुमिनसेंट होते हैं, जिनमें अंधेरे में प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है।

5. एक्साइज ज्यूटी

- उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर उनके उत्पादन, लाइसेंसिंग और बिक्री के लिए लगाया जाने वाला कर का एक रूप है।
- यह वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा भारत सरकार को दिया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष टैक्स है।
- उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क के विपरीत है क्योंकि यह देश में घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है, जबकि सीमा शुल्क देश के बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।
- केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आदि के रूप में लगाया जाता था।
- हालाँकि, जुलाई 2017 में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कई प्रकार के उत्पाद शुल्क शामिल हो गए। आज उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और शराब पर लगता है।



Mentorship
India

प्रीलिम्स ट्रेक

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 (1) को "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन" घोषित किया।
2. धारा 182(1) ने एक कंपनी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दान की जाने वाली धनराशि की सीमा तय कर दी
3. इस अनुभाग ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दान को कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 7.5% तक सीमित कर दिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ECI द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।
2. एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक आरक्षित प्रतीक होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।
3. पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए, यदि वह पार्टी दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ती है, तो चुनाव के दौरान एक मुफ्त प्रतीक को सामान्य प्रतीक के रूप में आवंटित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q3. निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल शिक्षा से संबंधित है?

1. प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
2. प्रज्ञाता
3. मध्याह्न भोजन योजना

ऊपर दिए गए विकल्पों में से कितने विकल्प सही हैं/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य-वित्त पोषित के साथ-साथ न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
2. 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
3. केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों का राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q5. हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रत्युष (PRATUSH) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

- A. यह मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की योजना है
- B. यह ग्रामीण स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने की योजना है
- C. सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई है
- D. RRI और इसरो द्वारा निर्मित भारत की प्रत्युष दूरबीन का उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के रहस्यों को उजागर करना है।

Q6. सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये कच्चे तेल के भंडार हैं जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय भी कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) से संबंधित प्रत्येक राष्ट्र को अपने शुद्ध तेल आयात के न्यूनतम 90 दिनों के बराबर तेल का आपातकालीन भंडार बनाए रखना आवश्यक है।
3. वर्ष 2017 में, भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के भीतर एक सहयोगी सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q7. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e2W) और तिपहिया वाहनों (e3W) की खरीद को बढ़ावा देने के लिए EMPS 2024 पेश किया है।
2. मुख्य लक्ष्य सब्सिडी पर उद्योग की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करते हुए e2Ws और e3Ws को अपनाना है।
3. इस योजना में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e4Ws) और ई-बसें शामिल नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q.8 पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह पश्चिमी घाट में स्थित है और सदाबहार वनों की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
2. यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और अपने शुष्क पर्णपाती जंगलों के लिए जाना जाता है।
3. यह भारत में बाघों की सबसे अधिक प्रजातियों का घर है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q.9 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को तीन सूचियों में विभाजित करता है
2. विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं पर खर्च ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है,
3. केंद्र सरकार रक्षा (लगभग दोगुना सामाजिक सेवाओं) और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर अधिक खर्च करती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q10. निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी झील है:

1. लहोनक झील
2. देवताल झील
3. कोलेरू झील

ऊपर दिए गए विकल्पों में से कितने विकल्प सही है/हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

प्रीलिम्स ट्रेक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प B सही है

व्याख्या

- चुनावी बॉन्ड (EB) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 (1) में निहित एक प्रावधान को हटाने को "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन" माना था। **इसलिए, कथन 1 गलत है।**
- अधिनियम की धारा 182 में कई बदलाव किए गए, जिसमें उन निषेधों और प्रतिबंधों का विवरण दिया गया है जिनका किसी कंपनी को राजनीतिक योगदान देते समय पालन करना चाहिए।
- संशोधन से पहले, धारा 182(1) में एक कंपनी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में दान की जाने वाली धनराशि की सीमा निर्धारित की गई थी।
- इसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 7.5% तक सीमित कर दिया गया।
- धारा 182(3) के तहत कंपनी को किसी भी राजनीतिक दल को दी गई किसी भी राशि का खुलासा करने के साथ-साथ दान की गई राशि का विवरण और प्राप्तकर्ता पार्टी का नाम बताना आवश्यक है, **इसलिए कथन 2 और 3 सही हैं**

उत्तर : 2 विकल्प C सही है

व्याख्या

- ECI द्वारा प्रतीक आदेश के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।
- सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां एक बड़ी आबादी अभी भी निरक्षर है, मतदान प्रक्रिया में प्रतीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का एक आरक्षित प्रतीक होता है जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाता है।
- पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव के दौरान मुफ्त प्रतीकों में से एक को सामान्य प्रतीक के रूप में आवंटित किया जाता है
- यदि वह पार्टी दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में या किसी राज्य की विधानसभा में 5% सीटों पर, जैसा भी मामला हो, चुनाव लड़ती है। **अतः सभी कथन सही हैं**

उत्तर : 3 विकल्प C सही है

व्याख्या

- शिक्षा से संबंधित सरकारी पहल
- प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- सर्व शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल **इसलिए सभी विकल्प सही हैं**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है

व्याख्या

- भारतीय संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 45 और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 39 (f) में राज्य-वित्त पोषित और साथ ही न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- वर्ष 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। **अतः कथन 1 और 2 सही हैं**
- केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित तीन-भाषा फॉर्मूला का पालन नहीं करता है। **इसलिए, कथन 3 गलत है**

उत्तर : 5 विकल्प D सही है

व्याख्या

- RRI और इसरो द्वारा निर्मित भारत की प्रत्युष दूरबीन का उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के रहस्यों को उजागर करना है।
- यह रेडियो टेलीस्कोप चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर स्थित होगा। पृथ्वी के हस्तक्षेप से बचने के लिए, चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित होने से पहले यह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- PRATUSH सबसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से आने वाले हल्के रेडियो संकेतों को सुनेगा। **इसलिए, कथन D सही है**

उत्तर : 6 विकल्प C सही है**व्याख्या**

- ये कच्चे तेल के भंडार हैं जो भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय भी कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखे जाते हैं।
- ये भूमिगत भंडारण सुविधाएं देश की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (IEP) समझौते की शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) से संबंधित प्रत्येक राष्ट्र को अपने शुद्ध तेल आयात के न्यूनतम 90 दिनों के बराबर तेल का आपातकालीन भंडार बनाए रखना आवश्यक है।
- वर्ष 2017 में, भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के भीतर एक सहयोगी सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

अतः सभी कथन सही हैं**उत्तर : 7 विकल्प C सही है****व्याख्या**

- भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e2W) और तिपहिया वाहनों (e3W) की खरीद को बढ़ावा देने के लिए EMPS 2024 पेश किया है।
- 5 अरब रुपये के बजट के साथ, यह FAME-2 योजना की जगह लेगी और अप्रैल से जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद इसे बदले जाने या बढ़ाए जाने की संभावना है।
- मुख्य लक्ष्य सस्ती पर उद्योग की निर्भरता को धीरे-धीरे कम करते हुए e2Ws और e3Ws को अपनाना है।
- इस योजना में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (e4Ws) और ई-बसें शामिल नहीं हैं।

अतः सभी कथन सही हैं**उत्तर : 8 विकल्प A सही है****व्याख्या**

- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में नहीं। यह सदाबहार नहीं बल्कि शुष्क पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है।
- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और अपने शुष्क पर्णपाती जंगलों के लिए जाना जाता है।
- अतः, कथन 2 केवल सही है
- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में भारत में बाघों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक नहीं है।
- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है।

उत्तर : 9 विकल्प C सही है**व्याख्या**

- इस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का सीमांकन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 59 विषयों (मूल रूप से 66) वस्तुओं की एक राज्य सूची शामिल है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु को तीन सूचियों के अंतर्गत विभाजित करता है
- संविधान भारत की संघीय सरकार (संघ) और राज्य सरकारों के बीच व्यय जिम्मेदारियों को विभाजित करता है।
- टैक्स में वृद्धि : अधिकतर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- स्पेंडिंग : अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है (संघ के ₹2,230 बिलियन की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹19,182 बिलियन)।
- सामाजिक सेवाओं बनाम अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दें:
- केंद्र सरकार रक्षा (सामाजिक सेवाओं से लगभग दोगुना) और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा (सामाजिक सेवाओं से 2.4 गुना) पर अधिक खर्च करती है।
- राज्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में सामाजिक खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस खर्च से धीमी ग्रामीण आय वृद्धि को संबोधित करने में मदद मिली है।

अतः सभी कथन सही हैं**उत्तर : 10 विकल्प B सही है****व्याख्या**

- भारत की सबसे ऊंची हिमानी झील देवताल, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है।
- दक्षिण लहोनाक झील एक हिमनद-मोराइन-बांधित झील है, जो सिक्किम के सुदूर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
- कोलेरू झील भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और एशिया में सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है, एलुरु से 15 किलोमीटर दूर और राजमहेंद्रवरम से 65 किलोमीटर दूर, यह झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। इसलिए, विकल्प 3 गलत है।

Mentorship India

Our mission is crystal clear – to provide the finest UPSC mentorship and guidance available in India. We recognize that the path to success in the UPSC examination is both demanding and multifaceted. This is precisely why we have developed a comprehensive approach that goes beyond conventional coaching. Our commitment lies in fostering excellence by equipping aspirants with the necessary tools, knowledge, and unwavering support to not only excel in the examination but also in life itself.

Mentorship India represents more than just an organization; it is a community of ambitious individuals bound together by the shared objective of conquering the UPSC examination. We warmly invite you to embark on this transformative journey alongside us. Whether you are a novice taking your initial steps or a seasoned aspirant aiming for the pinnacle, Mentorship India is your dependable companion in the relentless pursuit of excellence.

+91 9999 057869
www.mentorshipindia.com

A-92, Third Floor, Hari Nagar
Delhi - 110064

 @mentorship.india